<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2251

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सस्ते इस्पात का आयात

2251. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के कारण सस्ते इस्पात आयात से भारत के लिए कोई खतरा है;

(ख) क्या इस्पात विनिर्माताओं ने देश के हितों की रक्षा के लिए आरसीईपी सौदे से बाहर रहने के भारत के फैसले का स्वागत किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आरसीईपी में शामिल होने का विचार है, यदि भारत के नियम और शर्तें स्वीकार किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): चीन के पास इस्पात की अत्यधिक उपलब्धता के मद्देनजर, भारतीय इस्पात क्षेत्र को चीन से सस्ते इस्पात के आयात का खतरा हो सकता था। आरसीईपी के अंतर्गत, ऐसे आयातों को अधिमान्य प्रशुल्क (प्रेफेरेंशियल टैरिफ) का लाभ मिल जाता जिससे भारतीय इस्पात उद्योग को हानि होती। सरकार के आरसीईपी में शामिल न होने के निर्णय का स्वदेशी इस्पात उद्योग द्वारा स्वागत किया गया है।

4 नवंबर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि आरसीईपी के मौजूदा ढांचे में आरसीईपी के दिशानिर्देश पूरी तरह परिलक्षित नहीं होते हैं और इनसे लंबित मामलों और भारत की चिंताओं का समाधान नहीं होता है, और इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। भारत ने यह भी कहा कि एक्ट ईस्ट नीति भारत की आर्थिक नीति की आधारशिला है और अन्य व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध जारी रहेंगे।

****